

# माफ़ी की वह माँग तो भाव-विभोर करने वाली थी !



प्रधानमंत्री ने समूचे देश को आश्चर्यचकित करते हुए भाव-विभोर कर दिया। जनता इस तरह से भावुक होने के लिए तैयार ही नहीं थी। पिछले छह-सात सालों में 'शायद' पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 130 करोड़ लोगों से उन्होंने अपने 'मन की बात' इस तरह से बाँटी होगी। 'लॉक डाउन' से होने वाली दिक्कतों पर उन्होंने जो कुछ कहा वह चौंकाने वाला था। 'जब वे अपने भाई-बहनों की तरफ़ देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वे सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रधानमंत्री है जिसने हमें इतनी कठिनाइयों में डाल दिया है।'

देश में जो मौजूदा हालात हैं उन्हें देखते हुए भी प्रधानमंत्री से इस तरह की उदारता की उम्मीद किसी को नहीं थी। वह इसलिए कि पिछले वर्षों में कुछेक बार निश्चित ही ऐसी परिस्थितियाँ बन चुकी हैं कि सरकार के ही फैसलों के कारण जनता को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा है और उसके लिए कभी किसी भी कोने से कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं की गई। माफ़ी माँगना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती।

प्रधानमंत्री के 'मन की बात' को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि वे माफ़ी की माँग खुद के लिए नहीं बल्कि समूची सरकार, उसमें शामिल 'गो-कोरोना-गो' घटकों, स्वास्थ्य मंत्री और उस नौकरशाही के लिए कर रहे थे जो कि इतने बड़े वैश्विक संकट के दौरान ऊँघती हुई नहीं बल्कि सोती हुई पकड़ी गई है।

चीन के वुहान प्रांत में महामारी ने दिसम्बर में ही दस्तक दे दी थी। हमारे यहाँ 30 जनवरी को पहला केस दर्ज होने के बाद से 19 मार्च तक, जब कि प्रधानमंत्री ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए 22 मार्च को एक दिन के 'जनता कर्फ्यू' की घोषणा की थी, चीन में कोई तीन हज़ार से ज्यादा जानें चुकी थीं। महामारी तब तक अमेरिका और यूरोप के कई देशों में पैर पसार चुकी थी। कोई दो से ज्यादा महीनों का बहुमूल्य समय केंद्र और राज्यों की लचर व्यवस्था हज़म कर गई। यही वह वक्त था जब कि सारे इंतज़ाम होने थे।

कामों की असली शुरुआत पिछले दस-पंद्रह दिनों में हुई है या पहले से की जा रही थी समय आने पर पूछा ही जाना चाहिए। बचाव के उपकरणों की हकीकत केवल मोर्चे पर लगे चिकित्साकर्मी ही बता सकते हैं।

संकट से उबारने के तत्काल बाद, देश के सभी नागरिकों को केंद्र सरकार के साथ-साथ अपने-अपने सूबों

की हुकूमतों से विस्तृत 'श्वेत पत्रों' की माँग करनी चाहिए। इन 'श्वेत पत्रों' के ज़रिए उनसे माँग की जाए कि वे इन सत्तर दिनों में गुजरे हरेक घंटे में उनके द्वारा किए गए कामों का जनता के सामने ब्यौरा पेश करें। निरपराध लोगों की मौतों और जनता द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों का नैतिक भुगतान भी ज़रूरी है।

देश की जनता चाहे तो इस बात पर खेद व्यक्त कर सकती है कि अपने जिस 'गवर्नेन्स' को प्रधानमंत्री अपनी सबसे बड़ी ताकत मानकर चल रहे हैं उसी की लापरवाही के लिए उन्हें माफ़ी माँगनी पड़ रही है।

(श्री श्रवण गर्ग कई हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्रों के संपादक रह चुके हैं व राजनीतिक विश्लेषक हैं)